[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आपने आज बहुत कुछ किया है। बैठ जाइए, आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अन्याय हो रहा है, थोड़ा और टाइम होने दीजिए।

[अनुवाद]

देश के माननीय प्रधानमंत्री वित्तीय स्थिति पर वक्तव्य देना चाहते हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है परन्तु मेरा मानना है कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप इसे उठा सकेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी मैं अब आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा। मैं अब आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा। मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा – कृपया सभा से बाहर चले जाएं। यदि आप ठीक व्यावहार नहीं करेंगे तो कृपया बाहर चले जाइए। मैं ऐसा और नहीं चलने दूंगा। बहुत हो गया। यह बात खत्म हो गयी है।

जी हां, माननीय प्रधानमंत्री जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में कुछ तो शिष्टता होनी चाहिए। देश में प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं और आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मैं कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर उन्होंने स्वेच्छा से बोलने की बात की हैं और वह यह भी महसूस करते हैं कि इस पर वक्तव्य देना उनका कर्तव्य है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पता चलता है कि देश की वित्तीय स्थिति के संबंध में आपको कितनी चिन्ता है।

अपराह्न 4.02 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

विश्व में चल रहे वित्तीय संकट और भारत पर इसका प्रभाव

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं इस समय चल रहे विश्वव्यापी आर्थिक संकट और भारत पर उसके प्रभाव के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस आर्थिक संकट की शुरुआत अमरीका से हुई और यह तेजी से पूरे यूरोप में फैल गया। यह संकट आवास रेहन बाजार से शुरू हुआ और बढ़ते-बढ़ते मुद्रा बाजार और क्रेडिट मार्किट तक पहुंच गया। इसके परिणामस्वरूप बहुत से वित्तीय संस्थान दिवालिएपन की कगार पर पहुंच गए। अमरीका और कुछ अन्य विकसित देशों ने तमाम वित्तीय संस्थानों और बैंकों को इस वित्तीय संकट से उबारा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें। वे कभी भी परेशान नहीं हुए। कृपया यहां व्यवधान न पैदा करें।

डा. मनमोहन सिंह : उन्होंने तरलता लाने, बैंकों में पुन: पूंजी लगाने और क्रेडिट मार्किट को मंदी से उबारने के लिए अनेक परम्परागत कदम भी उठाए हैं। वित्तीय संकट की इस आंधी ने वित्तीय प्रणाली में आत्मविश्वास को हिला कर रख दिया है और इससे स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ गई है। इससे आर्थिक गतिविधियों में भारी मंदी आ गई है जिसका असर औद्योगिक देशों में दीर्घावधिक मंदी के रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत से पर्यवेक्षक इसे 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे खतरनाक संकट बता रहे हैं।

भारत, दूसरे विकासशील देशों की ही तरह इस वित्तीय संकट के प्रभावों का अनुभव कर रहा है। तथापि, हमने इस असर को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारी पहली चिंता यह सुनिश्चित

[डा. मनमोहन सिंह]

करना है कि हम अपनी बैंकिंग प्रणाली को स्थिर बनाए रखें। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली सबप्राइम मार्टगेज एसेट्स से सीधे रूबरू नहीं हुई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक वे अपनी बात समाप्त नहीं कर लेते तब तक आप प्रतीक्षा करें।

डा. मनमोहन सिंह : अन्य प्रॉब्लम एसेट्स से उनका सामना भी बहुत कम हुआ है। हमारे बैंक, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हों या निजी क्षेत्र के, दोनों वित्तीय रूप से मजबूत हैं, उनकी पूंजी पर्याप्त है और वे सुनियंत्रित हैं। किसी बैंक के असफल होने का कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं निवेशकों को खास तौर पर यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनकी जमा पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है।

हालांकि हमारे बैंक सुरक्षित हैं, और वे पूर्वानुमानित ऋण लक्ष्यों के अनुसार ऋण भी मुहैया करा रहे हैं, फिर भी, दुनिया भर में आई आर्थिक उथल-पुथल से अन्य वाणिज्यिक ऋणों में कमी आई है। कार्पोरेट सेक्टर द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले विदेशी वाणिज्यिक कर्ज समाप्त हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता ऋण समाप्त हो गया है। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में ऋण की समग्र उपलब्धता में कमी आई है। हालांकि वाणिज्यिक बैंकों से ऋण में संतोषजनक वृद्धि हुई है। इस से प्रणाली में वित्तीय संकट पैदा हो गया है।

इस समस्या के निदान के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। 6 अक्तूबर 2008 से 15 अक्तूबर 2008 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी जमा अनुपात सी.आर.आर. में कुल 250 बेसिस प्वाइंट तक कटौती की है। प्रारंभ में सांविधिक तरलता एस.एल.आर. जरूरतों में एक फीसदी प्वाइंट की छूट दी गई थी और बाद में खास तौर पर उसमें 0.5 फीसदी प्वाइंटस इन्ट्रोड्यूस शामिल किए गए थे ताकि बैंक म्यूचुअल फण्डों को लिक्वीडीटी प्रदान करने के लिए धनराशि निकाल सकें। इन उपायों के फलस्वरूप, भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकों की तरलता स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज कॉल मनी रेट लगभग 6.8 फीसदी है।

सरकार ने ऋण माफी और ऋण राहत योजना के तहत बैंकिंग प्रणाली के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम तौर पर देने की व्यवस्था की। निगमित बॉण्ड्स में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की सीमा 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से 6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की गई।

आज इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 100 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की घोषणा की। यह वह रेट है जिस पर बैंक अतिरिक्त एस.एल.आर. सिक्यूरिटी के ऊपर उधार ले सकते हैं। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्णय का स्वागत करती है। इसका ब्याज दर ढांचे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और तरलता बढ़ाने के दूसरे उपायों से आर्थिक गतिविधियों और निवेश को सहारा मिलेगा। यह व्यापक रूप से महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्यों के अनुरूप है जिसका असर दिखाई देने लगा है। माननीय सदस्यों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पहले तीन हफ्तों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में कमी आई है। हालांकि मौजूदा दर अभी भी ज्यादा है, फिर भी, मुद्रास्फीति की वर्तमान दरों में कमी आई है। हमें उम्मीद है कि अगले दो महीनों में थोक मूल्य सूचकांक में और कमी आएगी।

महोदय, सरकार इस सच्चाई से वाकिफ है कि धन मुहैया कराना ही काफी नहीं है। इसके जरिए उद्योग, व्यापार और व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध होना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित निर्देश दिए हैं कि उधार लेने वालों को पर्याप्त ऋण प्रदान किया जाए जिसमें निर्यात ऋण और कार्यशील पूंजी भी शामिल है। बैंकों को चाहिए कि वे निवेश अथवा ऋण के रूप में म्युचुअल फंडों और एन.बी.एफ.सी. को पर्याप्त धनराशि मुहैया कराएं ताकि बदले में वे उद्योगों, व्यापार और व्यवसाय को उधार दे सकें। ये संस्थाएं व्यापक वित्तीय प्रणाली व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और बैंको को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे धन मुहैया कराएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक क्रियाकलापों में कोई बाधा न पहुंचे।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ऋण के प्रवाह की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वित्तीय व्यवस्था में उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त धन के जरिए वास्तविक ऋण उपलब्ध हो। जरूरत पड़ने पर हम कुछ और कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जहां हमारे सभी बैंकों की पूंजी की उपलब्धता का अनुपात बेसल मानदण्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड से काफी ऊपर है, नहीं सरकार ने वादा किया है कि वह उन बैंकों की मदद करेगी जिनकी पूंजी की उपलब्धता का अनुपात कम है, ताकि उनकी सी.आर.ए.आर. में 12 फीसदी तक बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें धनराशि सुलभ हो सके।

विकसित देशों में आई आर्थिक मंदी और वित्तीय संकट का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की संभावना है। सौभाग्यवश, यह प्रभाव हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वर्ष 2008-09 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.9 फीसदी थी। अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान हमारा निर्यात डॉलर के हिसाब से 35.1 फीसदी बढ़ा। इस अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 14.8 बिलीयन अमरीकी डॉलर रहा। सकल कर राजस्व अपने निर्धारित लक्ष्य पर है। सी.एम.आई.ई. डॉटाबेस से पता चलता है कि पूंजी व्यय के लिए एक भारी भरकम धनराशि मौजूद है।

फिर भी, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली अस्थाई मंदी के लिए तैयार रहना चाहिए। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी अभी भी अनिश्चितता के दौर में है, इसलिए अभी हमारे ऊपर इस मंदी के प्रभाव की गहराई और अवधि का सही आकलन करन कठिन है। कुछ अनुमान इंगित करते हैं कि वर्तमान वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की दर घटकर 7.5 फीसदी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा यह 7 फीसदी तक गिर सकती है। हमारा प्रयास रहेगा कि वित्तीय संकट का नकारात्मक प्रभाव कम हो और विश्व के हालात स्थिर हो जाने पर हमारी अर्थव्यवस्था फिर से 9 फीसदी की दर से आगे बढ़ती रहे। माननीय सदस्यों और भारत के लोगों से मेरा आग्रह है कि वे भारत की अर्थव्यवस्था के मौलिक स्वरूप में अपना विश्वास रखें।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मंदी की प्रत्याशा में हमने 29 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत बजट में सरकारी व्यय में बढ़ोत्तरी की थी। हमारे व्यय प्रस्तावों की उस समय कुछ हलकों में आलोचना की गई थी। किन्तु मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाने लगा है कि सरकारी व्यय में वृद्धि करना इस समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं समझता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरन मिशन (जेएनएनयूआरएम) और अन्य कार्यक्रमों पर हमारा व्यय इस मुश्किल दौर में हमें मदद देगा। इसके अलावा, 3,60,00,000 किसानों को 65,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी और ऋण सहायता से हमारे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और वे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, भारत के सम्मुख पहले भी चुनौतियाँ आई हैं और उनका उसने मुकाबला किया है। हम मौजूदा चुनौतियों का भी सामना करने में समर्थ हैं। भारत के सामने जब भी चुनौतियां आई हैं भारत की जनता ने सामने आकर उन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में लिया है। भय के लिए कोई जगह नहीं है। यह समय उद्देश्यपरक एकता और संकल्प रूपी कार्रवाई करने का है। मैं सरकार तथा अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों के लिए इस माननीय सभा के सभी वर्गों का सहयोग चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8970-ए/08]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चित रूप से चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक-एक करके बोलने की कृपा करें तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पर आउंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। मैं आपकी बात पर आउंगा! मैं आप को आश्वासन दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाउंगा। मैं वादा करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाउंगा।